The quality of hides and skins available at these units will be better and could be converted into leather and leaher products for exports.

Riview of Ceiling on Cost of House

2181. SHRI JAGDISH TYTLER: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether Government are reviewing the question of ceiling on the cost of houses being built or financed by official agencies and also the income limits of various categories of people;

(b) if so, the details of its proposals; and

(c) when these are likely to be implemented?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) to (c). The Government has constituted a Group to examine the entire pattern of financing by the Housing and Urban Development Corporation Ltd. and to suggest changes considered necessary. The question of ceiling on cost of houses as well as income limits in relation to Hudco's programmes will be considered as soon as the group submits its recommendations.

उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली चीजें

2182. श्री रामावतार शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य राज्यों की तुलना में केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में उचित दर की दुकानों के माध्यम से अधिक चीजें दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उचित दर की दुकानों के माध्यम से दी जाने वाली वस्तुओं के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ग) केरल की तरह अन्य राज्यों में भी ये वस्तुएं उपलब्ध कराये जाने में क्या कठिनाई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रज मोहन महन्ती) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली की सलाहकार समितियों की बैठकें

2183. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों को आदेश जारी किए हैं कि उनकी सलाहकार समितियों की बैठकें भविष्य में केवल दिल्ली में ही आयोजित की जायें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । मितव्ययता के लिहाज से सभी मंत्रालयों/विभागों से हाल ही में यह निवेदन किया गया है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी परामर्शदात्री समितियों की कोई बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित न करें ।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को मंजूरी

2184. श्री रामावतार शास्त्री : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बिहार में बाढ़ों के नियंत्रण के लिए चार योजनायें मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक योजना को कार्यान्वित करने पर कितना व्यय किया जाएगा;

(घ) उक्त योजना कब आरम्भ की जाएगी; और इनको कब तक पूरा किया जाएगा; और

(ङ) उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद बिहार को क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग). चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की पांच बाढ़-नियंत्रण स्कीमें योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उम्मीद है कि ये स्कीमें इस वर्ष मानसून के बाद आरम्भ की जाएंगी और छठी योजनावधि के दौरान काफी हद तक पूरी हो जाएंगी।

विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभान्वित होने वाला क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या (लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	कमला–बालान तटबंध, चरण–एक का बजिया से कोठरम तक विस्तार . . .	493.71	0.24	3.302
2.	बिहार में गंडक के दायें किनारे पर पिपरासी–पिपराघाट क्षेत्र में 0 से 35 कि० मी० तक कटाव-रोधी वर्क्स और रिटायर्ड तटबंध .	392.67	1.09	1.325
3.	खुटाहा सुरक्षा वर्क्स . .	91.84	उपलब्ध नहीं	0.11
4.	तिमुहानी–कुरसेला तटबंध स्कीम	159.83	0.072	2.50
5.	बल्लाहपुर सुरक्षा वर्क्स .	136.57	उपलब्ध नहीं	.08